



- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशुतोष मोहले ने कहा वेक्स— दो हजार पच्चीस जैसी विभिन्न चुनौतियों से देश के युवाओं के लिए अनेक संभावनाएं सृजित होंगे।
- सांसद द्वारा भारत सरकार से केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने का आह्वान।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस द्वीपसमूह में कल लागू सत्रह फरवरी को मॉप अप किया जाएगा।
- देश में मौखिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया।



सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशुतोष मोहले ने तकनीकी क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान और नई सोच पर बल दिया है। आज नोएडा में आयोजित एक्स आर क्रिएटर हैकैथॉन—दिल्ली मीट अप को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वेक्स—2025 के तहत एक्स आर क्रिएटर जैसी विभिन्न चुनौतियों से देश में युवाओं के लिए अनेक संभावनाएं सृजित होंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेक्स 2025 और क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के साथ मिलकर एक्स आर क्रिएटर हैकैथॉन का आयोजन किया है। दो हजार दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने हैकैथॉन में भाग लिया। इनमें से चालीस प्रतिभागियों को फाइनल प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया।



सांसद ने भारत सरकार से केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय प्रमाण पत्र जारी करने के कार्यकारी निर्देश का समर्थन करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने का आह्वान किया है। इस अपील का उद्देश्य रोजगार और शिक्षा में द्वीपवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली सुनिश्चित करना है जो स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है। ये प्रमाण पत्र प्रशासन के भीतर रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए अनिवार्य है। स्थानीय आबादी पहले से ही क्षेत्र की दूरस्थता और सीमित अवसरों के कारण काफी चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकारी नौकरियों में स्थानीय वरीयता का मुद्दा, लंबे समय से मांग रहा है। सांसद ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि इस लंबित मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की जाए तथा रोजगार एवं शिक्षा के लिए स्थानीय प्रमाण पत्रों की कानूनी वैधता बहाल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाए।



शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा पे चर्चा के आठवें संस्करण के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। डॉ. बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में कल सुबह साढ़े दस बजे से इसका प्रसारण किया जाएगा। इसे द्वीपसमूह के छात्र, अभिभावक और शिक्षक देख सकेंगे। प्रधानमंत्री का संवाद दूरदर्शन के माध्यम से डी डी नेशनल, डी डी न्यूज और डी डी इंडिया चैनलों पर भी देखा जा सकता है।



राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस द्वीपसमूह में कल लागू किया जाएगा जिसके बाद सत्रह फरवरी को मॉप अप किया जाएगा। इस दौरान स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी। सभी अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोली दी जाए। आम जनता से भी अनुरोध किया गया है कि वे ए एन एम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को अपना सहयोग प्रदान करें तथा द्वीपसमूह में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रचार करें।



देश में मौखिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में एकीकृत, व्यापक मौखिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य मौखिक स्वास्थ्य देखभाल करना है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत संशोधित मौखिक स्वास्थ्य मैनुअल पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए हाल ही में ओगराब्राज सामुदायिक हॉल में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एक सौ नौ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों और समुदायों के बीच मौखिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना था। प्रतिभागियों को मौखिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर डॉ. संजीव जयचंद द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसमें मौखिक स्वच्छता, आहार और नियमित दंत जांच का महत्व शामिल था। डॉ. फरहीन कामिल ने अपने-अपने क्षेत्रों में मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और मौखिक रोगों की रोकथाम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।



प्रायागराज में चल रहे महाकुंभ में जल जीवन मिशन का पवेलियन लगाया गया है जिसमें ग्रामीण जीवन पर इस मिशन के प्रभाव को प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के ग्रामीण इलाकों में आ रहे बदलाव को भी प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है।



पशुपालन विभाग से किसानों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है। पोल्ट्री विकास कार्यक्रम द्वीपों में अत्यधिक सफल रहा है। मुर्गी पालन और द्वीपों में अंडे और मांस का उत्पादन राष्ट्रीय औसत से अधिक है। विभाग बेहतर पारिश्रमिक के लिए समर्पित बाजार के रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। इस दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, विभाग ने द्वीप समूह में स्वराज द्वीप की स्थानीय बत्तख नस्ल और शहीद द्वीप की बटेर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना शुरू की है। 'बत्तख और बटेर गाँव' पहल का उद्देश्य पर्यटन को स्थानीय किसानों से जोड़ना और आधुनिक पशुपालन प्रथाओं के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम टिकाऊ पशुपालन पर जोर देने, किसानों को सशक्त बनाने, बाजार के अवसर पैदा करने और सामुदायिक लचीलापन बनाने के लिए बनाया गया है। इस पहल के तहत चयनित किसानों की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इस परियोजना के पहले चरण के रूप में, विभाग ने इच्छुक किसानों को सात सौ बटेर और पांच सौ पैंतालिस बत्तख के चूजे वितरित किए हैं। यह पहल द्वीप समूह के कृषक समुदाय को सशक्त बनाने और क्षेत्र की आर्थिक और पोषण संबंधी भलाई को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को इस वर्ष अप्रैल से लेकर अगले वर्ष मार्च तक की रियायती चीनी का कोटा एक साथ प्रदान किया जाएगा। एक किलो चीनी प्रति कार्ड प्रतिमाह के हिसाब से वितरित की जाएगी। ऐसे सभी राशनकार्ड धारकों से अक्टूबर-फरवरी तक अपने दो महीने के राशन का कोटा उठाने को कहा गया है। हालांकि, जो राशन कार्ड धारक जनवरी के महीने में राशन नहीं ले पाए हैं, वे इस महीने अपना राशन ले सकते हैं।



इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय द्वारा छात्रों के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन और बी एस सी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हैं और पंजीकरण की अंतिम तिथि इक्कीस फरवरी है। इन कार्यक्रमों के लिए भुगतान केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा सोलह मार्च को होगी। ऑनलाइन फार्म भरने में यदि कोई कठिनाई आती है, तो श्री विजयपुरम के इग्नू के क्षेत्रीय केन्द्र से संपर्क किया जा सकता है।



भारत सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना में अठ्ठारह से चालीस वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड और प्राथमिक के.वाई.सी. दर्ज करानी होगी। पेंशन शुरू करने की आयु साठ वर्ष होगी। इसलिए इस योजना के तहत किसी भी ग्राहक द्वारा योगदान की न्यूनतम अवधि बीस वर्ष या उससे अधिक होगी। निश्चित न्यूनतम पेंशन लाभ

की गारंटी सरकार देगी। इस योजना के तहत द्वीपसमूह में अब तक तेरह हजार पांच सौ से अधिक व्यक्तियों का नामांकन हो चुका है।

<><><><><><><>

केन्द्रीय पुलिस सहायक भण्डार रेस्ट कैम्प बकुलतला में दूसरे एक्सटेशन काउंटर का हाल ही में उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन समारोह में दक्षिण अण्डमान पुलिस अधीक्षक श्वेता के. सुगथन के साथ अन्य आला-अधिकारी उपस्थित थे। इस काउंटर के खुल जाने से पुलिस कर्मियों की दैनिक खरीददारी को सरल बनाया जा सकेगा।

<><><><><><><>